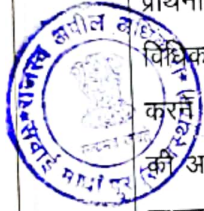


Form No. IIIफर्द अहकाम
(नियम 26)अज अदालत- राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर
मीठया वगै० बनाम गिर्राज वगै०

अपील संख्या 97/18 अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट

GCMS NO 2018/00207

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
6.8.25	<p>उभयपक्ष अधिवक्तागण उप०। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का दौराने बहस कथन रहा कि विवादित आराजीयात अपीलांट व रेस्पो० की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा रेस्पो० की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 13.7.18 को अंतरिम आदेश पारित किया है। जो विधि विरुद्ध है। जबकि अपीलांट विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.7.18 विधि विरुद्ध होने से अपास्त फरमाया जावे।</p> <p>जबाब मे रेस्पो० अधिवक्ता का कथन रहा कि अपीलांट द्वारा रेस्पो० के कब्जे काशत मे मजाहमत किये जाने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से रेस्पो० के कब्जे काशत मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अपीलांट को सही रूप से पाबन्द किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।</p> <p>उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील उप जिला कलेक्टर वामनवास के प्रकरण संख्या 51/08 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13.7.18 के विरुद्ध पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है जो पूर्ण निर्णय की श्रेणी मे नहीं आता है। विवादित भूमि अपीलांट व रेस्पो० की सहखातेदारी की आराजीयात होना उभयपक्ष का स्वीकृत तथ्य है। चूकि प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे अप्रार्थीगण से जबाब प्राप्त किया जाकर तथा प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दुओ का विवेचन कर अंतिम आदेश पारित किया जाना होता है। इस परिपेक्ष्य मे अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब अधिनस्थ न्यायालय मे नियत आगामी पेशी दिनांक 26.8.25 को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे एवं अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि जबाब प्रस्तुत होने पर विधि अनुसार उभयपक्ष को सुना जाकर अन्दर 2 माह मे प्रकरण का अंतिम निस्तारण करे। निर्णय सुनाया गया।</p>	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर